भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1661

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है ।

24 माघ, 1947 (शक)

ईसीएमएस के अपेक्षित प्रभाव का आकलन

1661. श्री सुभाष बरालाः
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः
श्रीमती संगीता यादवः
श्री रायगा कृष्णैयाः
श्री केसरीदेवसिंह झाला:
श्रीमती रेखा शर्माः
श्रीमती ममता मोहंताः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) के अपेक्षित प्रभाव का आकलन किया है;
(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रमुख परिणाम संकेतक कौन-कौन से हैं जिन पर नज़र रखा जाना है;
(ग) क्या उक्त योजना के लिए निगरानी एवं मूल्यांकन ढांचा निर्धारित किया गया है;
(घ) यदि हां, तो उक्त ढांचे का ब्यौरा क्या है;
(ङ) योजना के तहत आज की तारीख तक कितनी प्रगति हुई है; और
(च) ईसीएमएस के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण को बढ़ाने के लिए रोडमैप क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च): माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, भारत का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए संपूर्ण विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करना है। पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में काफी विस्तार हुआ है, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

#	2014-15	2024-25	टिप्पणियां
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन (रु.)	~1.9 लाख करोड़	~11.3 लाख करोड़	6 गुना वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात (रु.)	~0.38 लाख करोड़	~3.3 लाख करोड़	8 गुना वृद्धि
मोबाइल फोनों का उत्पादन (रु.)	~0.18 लाख करोड़	~5.5 लाख करोड़	28 गुना वृद्धि
मोबाइल फोनों का निर्यात (रु.)	~0.01 लाख करोड़	~ 2 लाख करोड़	127 गुना वृद्धि

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम को और सुदृढ़ और व्यापक बनाने के लिए, सरकार ने अप्रैल 2025 में **इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस)** शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य मूल्य श्रृंखला में निवेश (वैश्विक/घरेलू) को आकर्षित करके सुदृढ़ घटक विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करना

है, जिससे घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) में वृद्धि हो और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के साथ अपने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को एकीकृत करके वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में भारत के निर्यात की हिस्सेदारी में वृद्धि हो।

इस योजना के अंतर्गत भारत में घरेलू/वैश्विक निर्माताओं से 59,350 करोड़ रुपये के निवेश, 4,56,500 करोड़ रुपये के उत्पादन और 91,600 के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार की परिकल्पना की गई थी।

इस योजना को अब तक उद्योग से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। 59,350 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के सापेक्ष 1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश मूल्य वाली परियोजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

ईसीएमएस को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), पैसिव घटकों, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल घटकों, सब-असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, ऑप्टिकल ट्रांसीवर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान जैसे प्रमुख घटकों के घरेलू विनिर्माण की क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन घटकों का उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करेगा और इनमें से कई घटकों के लिए निर्यात क्षमता में वृद्धि करेगा।

ईसीएमएस योजना एक अखिल भारतीय पहल है, और विनिर्माण इकाइयों का स्थान उद्योग द्वारा तय किया जाता है।

अब तक 11 राज्यों में कुल 46 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। इनसे 54,567 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे 3,67,343 करोड़ रुपये का अनुमानित उत्पादन होगा और योजना अवधि के दौरान 50,794 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का अनुमान है।

ईसीएमएस योजना एक कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) है। पीएमए प्रस्तावों की जांच करता है और गवर्निंग काउंसिल (जीसी) को उचित सिफारिशें करता है। जीसी एक अंतर-मंत्रालयी परिषद है जिसकी अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव करते हैं और इसमें नीति आयोग, व्यय विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, दूरसंचार विभाग और भारी उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। जीसी प्रस्तावों की समीक्षा करता है और उचित सिफारिशें करता है।

बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के निर्माण का विस्तार करने के लिए ईसीएमएस के परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

*****